जवाहर लाल गुप्ता और एन. सी. खिची , न्यायमूर्तिगण ,के समक्ष

एन. के. धनराज,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और एक और,-उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. 5579 सन *1998*

30 सितंबर, 1998

सेना अधिनियम, *1950*-एस. 40 *(ए)* और *63-1* फरवरी, 1992 को धारा *40 (ए)* के तहत दी गई 'गंभीर फटकार' की सजा-बाद में कमांडिंग ऑफिसर ने आदेश दिया कि सजा धारा *63* के तहत दी गई मानी जाए और तदनुसार सर्विस बुक में एक प्रविष्टि की जाए-यह आदेश रद्द कर दिया गया और धारा *40 (ए)* के तहत मूल आदेश बहाल कर दिया गया-याचिकाकर्ता सेना प्रमुख को सजा कम करने के लिए वैधानिक शिकायत कर रहा है-कमांडिंग ऑफिसर शिकायत की सिफारिश कर रहा है *(*अच्छे आचरण, कड़ी मेहनत और भविष्य के करियर को ध्यान में रखते हुए*)* जिसे हालांकि *7* दिसंबर, *1995* को खारिज कर दिया गया-प्रतिनिधित्व के बावजूद प्रदान नहीं किए गए आदेश की प्रति-*1997* में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका-*12* फरवरी को याचिका खारिज कर दी।

मान लीजिए कि, घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि याचिकाकर्ता लगन से अपने उपचार का पीछा कर रहा था।वह खाली नहीं बैठा था।उन पर अनुचित देरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है ताकि उन्हें कानून के तहत राहत का दावा करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके। नतीजतन, प्रतिवादीगण की ओर से उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 40 के प्रावधान स्पष्ट हैं।जब भी सेना अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति "अपने वरिष्ठ अधिकारी पर आपराधिक बल का उपयोग करता है या हमला करता है", तो उसे "कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर" निर्धारित सजा दी जाएगी। यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता पर अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।हालाँकि, उनके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल कार्यवाही नहीं की गई थी।इस प्रकार, धारा 40 के तहत जुर्माना देने की मूल आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया।

(पैरा 8)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को दी गई 'गंभीर फटकार' का जुर्माना निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था।उचित अवसर से इनकार किया गया था।इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत उचित है।तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता को दिए गए जुर्माने को अलग कर दिया जाता है।प्रतिवादीगण अब उस तारीख से आगे की पदोन्नति के लिए अपने दावे पर विचार करेंगे जिस दिन से उनके कनिष्ठ व्यक्ति को उनके खिलाफ पारित दंड के आदेश की अनदेखी करके और प्रासंगिक रिकॉर्ड के आधार पर पदोन्नत किया गया था।

(पैरा 13)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद छिब्बर ने कहा,

कमल सहगल, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता**,** न्यायमूर्ति

(1) भारतीय सेना के याचिकाकर्ता को सेना अधिनियम, 1950 की धारा 40 (ए) के तहत 'गंभीर फटकार' का दंड दिया गया था।यह आदेश 1 फरवरी, 1992 को पारित किया गया था।कुछ महीनों के बाद, कमान अधिकारी ने आदेश दिया कि 'गंभीर फटकार' को धारा 63 के तहत दिया गया माना जाएगा।तदनुसार याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में एक प्रविष्टि की गई थी।हालांकि, कमांडिंग ऑफिसर द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया गया और 14 जुलाई, 1993 को 1 फरवरी, 1992 के मूल आदेश को बहाल कर दिया गया।याचिकाकर्ता ने सेना प्रमुख को "सजा कम करने के लिए" एक वैधानिक शिकायत दायर की।इस शिकायत की सिफारिश कमांडिंग ऑफिसर द्वारा "याचिकाकर्ता के अच्छे आचरण, कड़ी मेहनत और भविष्य के करियर को ध्यान में रखते हुए" की गई थी।हालांकि, सेना प्रमुख ने 7 दिसंबर, 1995 को वैधानिक शिकायत को खारिज कर दिया।इसके बाद याचिकाकर्ता ने विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।कोई जवाब नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के माध्यम से। 1997 की सिविल रिट याचिका संख्या 587।प्रतिवादीगण ने योग्यता के आधार पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया।हालांकि, 'क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र' के आधार पर याचिका की स्थिरता के बारे में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी।12 फरवरी, 1997 के आदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि "इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कभी भी कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, इसलिए याचिका को इस छोटे से आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।"इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

(2) इस याचिका का नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किया गया था।वे 15 जे. पी. एल. आई., 1998 को दिखाई दिए।दो बार मौका दिए जाने के बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।याचिका में बताए गए तथ्यों का खंडन नहीं किया गया है।

(3) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

(4) श्री.याचिकाकर्ता के वकील आनंद छिब्बर ने तर्क दिया है कि धारा 40 (ए) के तहत 'गंभीर फटकार' की सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कभी भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जैसा कि प्रावधान के तहत विचार किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावे का श्री सहगल ने खंडन किया है।दो गुना प्रस्तुति दी गई है। सबसे पहले, यह दावा किया जाता है कि याचिका में बहुत देरी हुई है।दूसरा, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को संक्षिप्त रूप से दंडित किया जा सकता था।

(5) गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, आपत्ति 9 एफ विलंब पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(6) घटनाओं का क्रम यह है कि सजा का आदेश फरवरी * 1992 में पारित किया गया था।हालांकि, कमांडिंग ऑफिसर ने स्वयं आदेश को संशोधित करना उचित समझा था और 'गंभीर फटकार' की सजा जो शुरू में धारा 40 (ए) के तहत दी गई थी, धारा 63 के तहत दी गई थी। नतीजतन, सजा में कमी आई।यह स्वीकार किया जाता है कि जबकि धारा 40 (ए) के तहत याचिकाकर्ता तीन साल की अवधि के लिए पदोन्नति के लिए अयोग्य हो सकता था, धारा 63 के तहत केवल एक साल की अवधि के लिए बार बनाया जा सकता था।प्रतिवादीगण की ओर से इस तथ्यात्मक स्थिति पर कोई विवाद नहीं हुआ है।इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा के संबंध में पत्राचार जारी रहा था और-15 मई, 1993 के पत्र के माध्यम से, कमांडिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड ऑफिस से अनुरोध किया था कि "मामले को अनुकूल रूप से देखें और नए मामले के अनुसार नियत तारीख को हवलदार के पद पर पदोन्नति के लिए एन. सी. ओ. (याचिकाकर्ता) पर विचार करें" इस संचार की एक प्रति अनुलग्नक पी/2 के रूप में प्रस्तुत की गई है। यह भी उल्लेख करने योग्य है कि इस पत्र में यह विशेष रूप से लिखा गया है

उल्लेख किया कि "व्यक्ति (याचिकाकर्ता) को 1 फरवरी, 1992 को सेना अधिनियम की धारा 40 (ए) के तहत तत्काल 'गंभीर फटकार' दी गई थी।अन्यथा एन. सी. ओ. बहुत ईमानदार, ऊर्जावान और

मेहनती है "क्योंकि" एन. सी. ओ. द्वारा किया गया अपराध एक नियमित सैन्य प्रकृति का था, यह सीएम (कोर्ट मार्शल) द्वारा मुकदमे के लिए योग्य नहीं था।इस प्रकार ओ. सी. (ऑफिसर कमांडिंग) की संक्षिप्त शक्तियों के तहत इसका निपटारा किया गया था।हालाँकि, धारा 40 (ए) का परिणाम जो उन्हें तीन साल के लिए आगे की पदोन्नति से रोकता है, अनजाने में आरोप तैयार करने के समय कल्पना नहीं की जा सकी "इस प्रकार, याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए एक सिफारिश की गई थी।हालांकि, इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।वास्तव में, 14 जुलाई, 1993 के पत्र के माध्यम से, कमांडिंग ऑफिसर को फरवरी, 1992 में पारित आदेश की बहाली से संबंधित निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया था।इस आदेश के बारे में पता चलने के बाद याचिकाकर्ता ने 2 दिसंबर, 1993 को एक वैधानिक शिकायत प्रस्तुत की थी।इस प्रशंसा को 7 दिसंबर, 1995 को अस्वीकार कर दिया गया था।हालाँकि, याचिकाकर्ता को 16 अप्रैल, 1996 को इस आदेश से अवगत कराया गया था।इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ आयोजित कार्यवाही की प्रति की आपूर्ति के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।उन्होंने 18 नवंबर, 1996 को एक और ज्ञापन प्रस्तुत किया था।जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।यह रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष 12 फरवरी, 1998 तक लंबित रही।याचिका को खारिज करते समय भी, यह देखा गया था कि "जिस न्यायालय के समक्ष अब याचिका दायर की जाएगी, वह निश्चित रूप से इस तथ्य का ध्यान रखेगा कि यह याचिका इस न्यायालय में दायर की गई थी और इन सभी दिनों तक लंबित रही।" इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 1998 में इस न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत की गई।

(7) घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि याचिकाकर्ता अपने उपचार को कमजोर कर रहा था।वह खाली नहीं बैठा था।उन पर अनुचित देरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है ताकि उन्हें कानून के तहत राहत का दावा करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके।नतीजतन, प्रतिवादीगण की ओर से उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है।

(8) जहाँ तक गुण-दोष पर विवाद की बात है, धारा 40 के प्रावधान स्पष्ट हैं।जब भी सेना अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति "अपने वरिष्ठ अधिकारी पर आपराधिक बल का उपयोग करता है या हमला करता है", तो उसे "कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर" निर्धारित सजा दी जाएगी। वर्तमान मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं पर उनके वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।हालाँकि, उनके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल कार्यवाही नहीं की गई थी।इस प्रकार, धारा 40 के तहत जुर्माना देने की मूल आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया।

(9) श्री सहगल प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता पर संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया गया था।यह कार्रवाई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप थी। हालांकि, विद्वान वकील अपनी प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए इस मामले की फाइल पर कुछ भी संदर्भित करने में सक्षम नहीं है।वास्तव में, इस फाइल का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से उनके तर्क को गलत साबित करता है।याचिकाकर्ता के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा 15 मई, 1993 को भेजे गए पत्र का अवलोकन पेपर बुक के अनुलग्नक पी2 में है।इस संचार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेना अधिनियम की धारा 40 (ए) के तहत 1 फरवरी, 1992 को "व्यक्ति को गंभीर फटकार" दी गई थी।यह भी देखा गया है कि "धारा 40 (ए) के तहत अपराधों पर आम तौर पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाता है।"प्राधिकरण ने आगे देखा कि "चूंकि एन. सी. ओ. द्वारा किया गया अपराध एक नियमित सैन्य प्रकृति का था, इसलिए यह मुख्यमंत्री (कोर्ट मार्शल) द्वारा मुकदमे के लिए योग्य नहीं था।" इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सजा "पल भर में" दी गई थी।याचिकाकर्ता के लिए कोई उचित अवसर नहीं था।

(10) श्री सहगल का तर्क है कि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र आदि दिया गया था और उस पर संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया गया था।इस संबंध में, यह उल्लेख करने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने 15 नवंबर, 1996 के अपने अभ्यावेदन के माध्यम से, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-9 के रूप में प्रस्तुत की गई है, अधिकारियों से आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी और सेना नियम 184 के अनुसार साक्ष्य का सारांश प्रदान करने का अनुरोध किया था।उसने भुगतान करने की पेशकश भी की थी।हालांकि, इन्हें आपूर्ति नहीं

की गई थी।रिकॉर्ड कार्यालय को संबोधित एक अन्य संचार द्वारा अनुरोध को दोहराया गया था। लेकिन सफलता नहीं मिली।इस स्थिति में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को उचित अवसर से वंचित किया गया था।

(11) इस याचिका के लंबित रहने के दौरान भी जब प्रतिवादीगण ने जवाब दाखिल करने में समय लिया था, श्री छिब्बर ने बताया कि याचिकाकर्ता पर रिट याचिका वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था।यह भी कहा गया कि उनकी गोपनीय रिपोर्ट को भी मामले को वापस लेने से इनकार करने के कारण खराब कर दिया गया था।ये आरोप अदालत में लगाए गए थे।हम इस विवाद में यह देखने के अलावा नहीं जाना चाहेंगे कि प्रत्येक नागरिक को कानून के अनुसार अपना उपाय मांगने का अधिकार है और किसी को भी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि कोई प्राधिकारी किसी अधीनस्थ पर मामला वापस लेने के लिए दबाव डालता है या ऐसा करने से इनकार करने के कारण उसे प्रतिकूल रिपोर्ट देता है।इस स्तर पर हम और कुछ नहीं कहेंगे।

(12) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता को दी गई 'गंभीर फटकार' का जुर्माना निम्नलिखित के अनुरूप नहीं था। उचित अवसर से इनकार किया जा रहा था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत उचित है।तदनुसार रिट याचिका की अनुमति है। याचिकाकर्ता को दिए गए जुर्माने को अलग कर दिया जाता है।प्रतिवादीगण अब उनके बारे में विचार करेंगे।आगे की पदोन्नति के लिए दावा उस तारीख से प्रभावी है जब उसके कनिष्ठ व्यक्ति को उसके खिलाफ पारित दंड के आदेश की अनदेखी करके और प्रासंगिक रिकॉर्ड के आधार पर पदोन्नत किया गया था।इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने पर तीन महीने के भीतर आवश्यक कार्य पूरा कर लिया जाएगा।इसके बाद परिणामी लाभ मिलेंगे।याचिकाकर्ता अपनी लागतों का भी हकदार होगा जिसका आकलन रु। 5000।

आरएनआर

***अस्वीकरण :*** *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा